[श्री भूपेन्द्र यादव]

उच्च उपयोग और प्रबन्धन भी राज्यों का विषय है, परन्तु इस संकट की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए cooperative और प्रतिस्पर्धी संवाद की भावना में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आयी है, उसके माध्यम से पूरे देश में पहल होनी चाहिए।

महोदय, अभी राम नाथ ठाकुर जी ने बिहार का एक विषय उठाया था। हालांकि बिहार में काफी सारी नदियां भी हैं, परन्तु इस समय जो जल प्रबंधन है, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, हमारे कृषि उत्पादन का 20 से 30 प्रतिशत जो हिस्सा है, यह उसी जगह से आता है। पानी का यह जो संकट है और जो भूजल का गिरता हुआ जल-स्तर है, उस पर जो सीमित कार्रवाई है, यह आने वाले समय में पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पर संकट भी खड़ा कर सकती है। इसलिए जल-संसाधन की सीमित उपलब्धता और पानी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में तुरन्त हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भूजल के प्रभावी संरक्षण हेतु उपयुक्त रणनीति को तैयार करने और कार्यान्वित करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे आने वाले वर्षों में जल-संकट ज्यादा भयानक रूप न ले पाए। पूरे देश में सभी विषयों से ऊपर उठकर, विशेष रूप से नगरीय नियोजन और शहरों में आज जिस प्रकार से पानी की खपत बढ़ रही है, यदि हमें पीने के पानी के लिए भी बांधों का उपयोग करना है तो कृषि, जल और शहरी प्रबंधन तीनों में एक समन्वय बनाना होगा। जल प्रबंधन समग्र सूचकांक की दिशा में जो हमारी नीतियां हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उसे आगे बढ़ाते हुए, भविष्य में जल-संसाधनों की उपलब्धता को हमें सुनिश्चित करना होगा।

श्री राम विचार नेताम : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री नारायण लाल पंचारिया: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती रूपा गांगुली: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

Strike declared by the All India Motor Transport Congress

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, there is a truckers' strike going on in the country. This is a matter of great concern because this is slowing down the economy, affecting multiple sectors, including consumers. if there is no movement of finished goods; the farmers if there is no movement of perishable items and, of course, labour who are involved in this large industry. The truckers' main demands are that issues related to passage of goods between the States is being slowed down by an E-Way Bill which is not being implemented properly and which hampers the passage of trucks and

is resulting in tremendous losses to the trucking industry, Because of the barriers that they face and the delays at toll barriers, a huge amount of fuel is wasted by the trucking industry. The truckers' industry has already met the Ministers concerned but they are not satisfied with the response of the Ministers.

I urge the Government and the Ministers concerned to be much more pro-active in responding to the truckers' strike. This is not a stage of the economy where we can afford any slow down. So, please consider the challenges introduced by the implementation of the GST in the context of E-Way Bills, etc., and provide remedy to the problems faced by the truckers and ensure that the strike can be called off as speedily as possible, and all the collateral damage caused by this very, very significant strike is remedied right away.

DR. SANJAY SINH (Assam): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RANJIB BISWAL (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश)**:** महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री नारायण दास गुप्ता: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir we also associate our selves with the matter raised by the non. Member.

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Minister.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): चेयरमैन सर, छत्रपति साहू महाराज जी ने 1902 में पूरे मराठा समाज, बहुजन समाज और दलित समाज को आरक्षण दिया था। आज उसे 116 साल पूरे हो रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप विषय पर कहिए।

श्री रामदास अठावलेः आज साहू महाराज की याद में हमने वहां ...**(व्यवधान)**... स्मारक बना दिया है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: He is talking about Sahu Maharaj....*(Interruptions)*...

श्री रामदास अठावलेः साहू महाराज ने आज से 116 साल पहले जो आरक्षण दिया था, ...**(व्यवधान)**... मैं सदन को जानकारी दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... महाराष्ट्र में आज मराठा आन्दोलन भी चल रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि मराठा समाज, जाट समाज, पाटीदार समाज और ब्राह्मण समाज, ...**(व्यवधान)**... इन्हें आरक्षण देने संबंधी कानून बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सूचित करना चाहता हूं।

SPECIAL MENTIONS

श्री सभापतिः ठीक है। ...**(व्यवधान)**... Now, Special Mentions. Shri Narayan Lal Panchariya, you can read.

Demand to take action against the industrial units and urban authorities in Punjab responsible for allowing polluted water to flow into the Harike Barrage which is main source of water supply to Rajasthan

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान)**:** सभापति महोदय, राजस्थान अपने हिस्से का रावी, व्यास और सतलुज का जल हरिके बैराज की डाउनस्ट्रीम से प्राप्त करता है परन्तु पंजाब राज्य में नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट नालों से होते हुए अंततः सतलुज नदी में मिलकर हरिके बैरात में आता है। हरिके बैराज में आया हुआ जल राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर में छोड़ा जाता है। राजस्थान फीडर से विशेषकर राजस्थान को पानी मिलता है तथा फिरोजपुर फीडर पंजाब और राजस्थान की संयुक्त नहर है, जिससे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को जल आपूर्ति होती है। हरिके बैराज से राजस्थान को हो रही जलापूर्ति की गुणवत्ता अत्यधिक प्रदूषित है। इस विष्य में समय-समय पर राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब सरकार को अनुरोध किया गया है कि हरिके बैराज पर प्रदूषित जल प्रवाहित करने के मुद्दे पर ठोस कदम उठा कर इसका निवारण करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जुलाई, 2017 में जल संसाधन विभाग, राजस्थान एवं पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सतलुज नदी तथा इसके कई स्रोतों पर संयुक्त रूप से मॉनीटरिंग की गई। जब फिरोजपुर फीडर में जल गुणवत्ता की जांच की गई, तो इसमें प्रदूषक तत्वों की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक थी।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से यह निवेदन करता हूं किं पंजाब के औद्योगिक न नगरीय प्राधिकरणों, जो कि राजस्थान को आपूर्ति हो रहे जल को प्रदूषित करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाए, जिससे राजस्थान की जनता को शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।